CENTRE FOR CIVIL SOCIETY
Social Change Through Public Policy

प्रेस विज्ञप्ति

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 10 पायदान फिसला

- फ्रेजर इंस्टिट्यूट व सेंटर फॉर सिविल सोसायटी द्वारा जारी वैश्विक रैंकिंग में 102 से फिसलकर 112वें स्थान पर पहुंचा भारत
- आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में भूटान (78), नेपाल (108) व श्रीलंका (111) से पिछड़ा पर चीन (113), बांग्लादेश (121) व पाकिस्तान (133) से रहा आगे
- आर्थिक रूप से स्वतंत्र देशों की सूची में हांगकांग शीर्ष पर, सिंगापुर व न्यूजीलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर

नई दिल्ली। फ्रेज़र इंस्टिट्यूट, कनाडा द्वारा जारी वार्षिक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सूची (इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स लिस्ट) में भारत दस पायदान फिसलकर112 वें क्रम पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष जारी सूची में भारत की रैंकिंग 102 थी। आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 159 देशों की सूची में में भारत को112 वें क्रम पर रखा गया है। पड़ोसी देश भूटान ,नेपाल व श्रीलंका क्रमशः78 वें ,108वें व111 वें क्रम के साथ सूची में भारत से ऊपर हैं जबकि चीन ,बांग्लादेश व पाकिस्तान को सूची में भारत से नीचे स्थान मिला है और उनकी रैंकिंग क्रमशः113 , 121व 133 है। सूची में हांगकांग को फिर से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।

बृहस्पतिवार को फ्रेज़र इंस्टिट्यूट ,कनाडा व उसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा **'इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड'** रिपोर्ट को विश्वभर में जारी किया गया। भारत में फ्रेज़र इंस्टिट्यूट की सहयोगी संस्था थिंकटैंक **सेंटर फॉर सिविल सोसायटी** है। यह रैंकिंग दुनिया भर से जुटाए गए वर्ष 2014 के आंकड़ों पर आधारित है। रैंकिंग प्रदान करने के लिए देश में सरकार के आकार (साइज ऑफ गवर्नमेंट), कानून प्रणाली और संपत्ति के अधिकार (लीगल सिस्टम एंड प्रॉपर्टी राइट्स), मौद्रिक नीति (साउंड मनी), वैश्विक व्यापार की आजादी (फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली) व नियमन (रेग्युलेशन) को आधार बनाया जाता है। भारत का प्रदर्शन सरकार के आकार को छोड़ अन्य सभी वर्गों में खराब रहा है। सरकार के आकार के हिसाब से भारत विश्व में 8वें स्थान पर है किंतु कानून प्रणाली और संपत्ति के अधिकार, मौद्रिक नीति, वैश्विक व्यापार की आजादी, नियमन आदि वर्गों में इसका प्रदर्शन अत्यंत खराब रहा है और इसे क्रमशः 86वां, 130वां, 144वां व 132वां स्थान प्राप्त हुआ है।

फ्रेज़र इंस्टिट्यूट के साथ सुंयक्त रूप से रिपोर्ट जारी करते हुए सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के प्रेसिडेंट **डा .पार्थ जे .शाह** ने कहा कि उच्च आर्थिक स्वतंत्रता का सीधा संबंध नागरिकों की समृद्धि और जीवन की उच्च गुणवत्ता से है। जबकि कम आर्थिक स्वतंत्र देशों में प्रायः नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों को दबाने की प्रवृत्ति होती है।

वर्तमान सूची में हांगकांग के बाद सिंगापुर ,न्यूजीलैंड ,स्विट्जरलैंड ,कनाडा ,जॉर्जिया ,आयरलैंड ,मॉरिसस व संयुक्त अरब अमीरात को क्रमशः दूसरे ,तीसरे ,चौथे ,पांचवें ,छठें ,सातवें ,आठवें व नौवें स्थान पर रखा गया है। दसवें स्थान के लिए ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच टाई हुआ है।

सूची में अंत के दस देश क्रमशः ईरान ,अल्जीरिया ,चाड ,गुएना ,अंगोला ,सेंट्रल ऐफ्रिकन रिपब्लिक ,अर्जेंटिना , रिपब्लिक ऑफ कांगो ,लिबिया और वेनेजुएला हैं। जबकि अन्य महत्वपूर्ण देशों जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जर्मनी , जापान ,फ्रांस ,रूस को सूची में क्रमशः16 वें ,30वें ,40वें ,57वें और 102 स्थान पर रखा गया है।

रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ने के लिए क्लिक करें.. http://www.freetheworld.com/release.html

सीसीएस के बारें में

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की एक स्वतंत्र, लाभ न कमाने वाला, अनुसंधान और शैक्षणिक थिंकटैंक सेंटर है, जो नागरिक समाज को पुर्नजीवित करते हुए और राजनीतिक समाज की पुनर्रचना केद्वारा भारत के समस्त नागरिकों के लिए अवसर और समृद्धि बढ़ाने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार

BOARD OF TRUSTEES

Luis Miranda, Chairman
Parth J Shah, President
Ankur Shah
Ashish Dhawan
Gurcharan Das
Iris Madeira
Premila Nazareth

ADVISORS

Amit Kaushik
Madhav Chavan
Praveen Chakravarty
Reuben Abraham

SCHOLARS

Ajay Shah
Deepal Lal
Isher J Ahluwalia
Jagdish Bhagwati
Leland Yeager
Lord Meghnad Desai
Shreekant Gupta
Surjit Bhalla
Swaminathan Aiyar
Urjit Patel

Contact Us:
A-69, Hauz Khas
New Delhi 110016
Tel: +91 11 2653 7456
2652 1882
Fax: +91 11 2651 2347
Email: ccs@ccs.in

www.ccs.in
www.azadi.me

शिक्षा के क्षेत्र में बाजार आधारित समाधान और नवीनतापूर्ण सामाजिक समुदायिक संसाधन बनकर लोकनीति के जरिये सुधार लाना है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेः
अविनाश चंद्र, +91 9999 88 2477, avinash@ccs.in